RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 01 FEBRUARY TO 07 FEBRUARY 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 20 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

बदल रहा है भारत! तेल खरीदने वाला देश अब प्लेन का फ्यूल कर रहा एक्सपोर्ट Page 2

इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपों 2023 10- 13 फरवरी 2023 तक इंदौर में Page 3

निर्मला के बजट में मिडिल क्लास, महिला, वेतनभोगियों के लिए बल्ले-बल्ले Page 4

editoria!

संयुक्त राष्ट्र में सुधार

भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने यहां जिस शिद्दत से सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठाया, वह गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपने मौजूदा रूप में पंगु हो चुका है। हालांकि सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा कोई नया नहीं है। भारत सहित कई अन्य देश पिछले कई वर्षों से इसकी मांग करते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एकाधिक अवसरों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों से इस बारे में आवाज उठा चुके हैं। कुछ ही दिनों पहले वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि संयुक्त राष्ट्र 1945 में बनाया गया एक 'फ्रोजेन मैकेनिज्म' बनकर रह गया है। दिक्कत यह रही कि भारत की ओर से उठाई जा रही इस मांग को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने की उसकी आकांक्षा से जोड़कर देखा जाता रहा है। नतीजा यह हुआ कि अलग-अलग मौकों पर विभिन्न देश संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत को समर्थन का आश्वासन देते रहे, लेकिन वे इस मसले पर गंभीर नहीं हुए। इसीलिए अलग-अलग मंचों से इस मुद्दे के उठने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र महासभा में कभी इस आशय का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। मगर यूक्रेन युद्ध ने इस अंतरराष्ट्रीय संस्था की बढ़ती अप्रासंगिकता को एक झटके में उजागर कर दिया। खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया गवाह है, कैसे सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य (रूस) ने अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण किया, उसकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया और सुरक्षा परिषद कोई फैसला नहीं कर सकी। कारण रहा उस सदस्य की वीटो पावर। साफ है कि जो वीटो पावर सुरक्षा परिषद के पांचों सदस्यों को इस मकसद से दी गई थी कि यह संस्था ज्यादा कारगर हो और दुनिया को युद्ध से बचाए, वही अब इस संस्था के पैरों की बेड़ी साबित हो रही है। अब इसमें जरा भी शक नहीं रह गया है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर और उसके कामकाज में दुनिया की मौजूदा भू-राजनीति की हकीकत नहीं झलकती। लेकिन बाधा अब भी सबसे बड़ी वही है, सदस्य राष्ट्रों में एकमत का अभाव। जानकारों के मुताबिक, अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य राष्ट्रों के बीच पांच नेगोशिएटिंग ग्रुप सक्रिय हैं और वे सब एक-दूसरे की काट बने हुए हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर सुधार का अजेंडा आगे बढ़ाने का वास्तविक दबाव तभी बनेगा, जब महासभा की ओर से उन्हें प्रस्ताव भेजा जाएगा। चूंकि यही नहीं हो रहा तो बात आगे नहीं बढ़ रही। बहरहाल, भारत जैसे देश का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा काफी मजबूत है। वह सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ दुनिया की पांचवीं बड़ी इकॉनमी भी है। इसलिए उसे यह सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब इसके लिए रिफॉर्म्स हों। इन सुधारों की बदौलत ही संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता बनी रहेगी।

सैलरीड क्लास की 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री

नई टैक्स रिजीम के स्लैब भी बदले

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को राहत तो दी, लेकिन उनको... जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे। पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको ऐसे समझें... 7.5 लाख रुपए सैलरी पर पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा लें। बचे 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए होते ही आप रिबेट के दायरे में आ जाएंगे और पूरी टैक्स छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा हुई तो टैक्स चुकाना होगा। नए टैक्स सिस्टम के लिए वित्त मंत्री ने नए स्लैब्स का भी ऐलान कर दिया है। उनके लिए अब 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी।

हायर सरचार्ज 37% से घटाकर 25%

ज्यादा आमदनी वालों के लिए टैक्स रेट 42.74% है। इसे अब घटाकर 37% किया जा रहा है। दरअसल, सुपर रिच लोगों के लिए हायर सरचार्ज रेट को 37% से घटाकर 25% किया गया। इस तरह पहले 42.74% लगने वाला सुपर रिच टैक्स अब 37% होगा।

रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट पर छूट की लिमिट बढ़ी

प्राइवेट कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट में आयकर छूट की सीमा तीन लाख रुपये तय की गई थी। उस वक्त सरकार में हाई बेसिक पे 30 हजार रुपए होती थी। इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जा रहा है। यानी 25 लाख रुपए तक के लीव एनकैशमेंट पर टैक्स नहीं लगेगा।

नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट किया जाएगा

नए इनकम टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया जाएगा। यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जब आप रिटर्न भरने पोर्टल पर जाएंगे तो नया टैक्स सिस्टम पहले से ही सेलेक्ट दिखेगा। पुराने टैक्स सिस्टम पर जाने के लिए आपको उसे क्लिक करके चुनना होगा।

पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख से ज्यादा इनकम पर टैक्स

पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख - 2.5 लाख = 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होगा। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का फायदा उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की - सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकेंगे।

सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है, पर इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है। मतलब यह कि अगर किसी की सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर आपकी कमाई 5 लाख 10 हजार रुपए हुई तो आपको 10 हजार रुपए पर टैक्स देने के बजाय 5.10 लाख - 2.5 लाख = 2.60 लाख पर टैक्स देना होता है।

फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन

इनकम टैक्स रिटर्न यानी ध्ऊँ फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। सरकार ने नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन कर दिया है । यानी बजट में इनकम टैक्स से दी गई राहत सिर्फ इसी पर लागू होगी। अगर आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको ये राहत नहीं मिलेगी। यदि आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको अपने निवेश के लिए सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे और पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा।

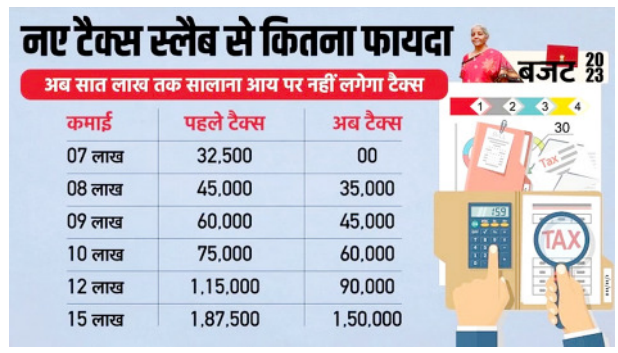

बजट में क्या महंगा क्या सस्ता

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

देश के आम बजट 2023 में देसी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन सस्ते; सिगरेट, चांदी और किचन चिमनी महंगी हुई और आने वाले दिनों में मोबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है, वहीं सोना-चांदी खरीदना महंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और सोना-चांदी पर ड्यूटी में इजाफा किया है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर किन चीजों का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, जानते हैं क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा...

सस्ता

■लिथियम आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल सामान की इंपोर्ट ड्यूटी घटाई। इससे EV सस्ते होंगे। ■टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% की गई। ■मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई। ■हीट कॉइल पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% कर दी गई है। ■लैब में बने हीरों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल सीड पर ड्यूटी कम की। ■एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए श्रिंप फीड पर कस्टम ड्यूटी कम करेगी। ■क्रूड ग्लिसरीन पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से घटाकर 2.5% की गई■ क्लीनिंग एजेंट डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल से कस्टम ड्यूटी खत्म की गई

महंगा

■सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आपात ड्यूटी (NCCD) को 16% बढ़ाया ■गोल्ड बार और प्लेटिनम से बने सामान की ड्यूटी बढ़ाई ■चांदी की ड्यूटी 6% से 10% की। उससे बने सामान पर भी ड्यूटी बढ़ाई ■कंपाउंडेड रबर पर ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% किया ■किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% की गई ■अब बात उएऊ की जिसके दायरे में 90% प्रोडक्ट आते हैं...

ऐसे कम ही प्रोडक्ट है जो बजट में सस्ते या महंगे होने जा रहे हैं। इसका कारण है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST। 2017 के बाद लगभग 90% प्रोडक्ट की कीमत GST पर निर्भर करती है, जिसे GST काउंसिल तय करती है। (विस्तृत समाचार पृष्ठ 4 पर)

बदल रहा है भारत! तेल खरीदने वाला

देश अब प्लेन का फ्यूल कर रहा एक्सपोर्ट, कंपनी ने किया कमाल

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

विदेशों से कच्चा तेल खरीदने वाला भारत अब प्लेन का फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने विमान ईंधन गैसोलीन का निर्यात शुरू कर दिया है। यह मानव रहित विमानों और छोटे विमानों को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) से विमान गैस की 80 बैरल की पहली खेप पापुआ न्यू गिनी के लिए भेजी गई थी। भारत अब इस ईंधन के लिए अनुमानित 2.7 अरब डॉलर के वैश्विक बाजार में प्रवेश कर रहा है। इसे पहली बार आईओसी की वड़ोदरा रिफाइनरी में उत्पादित किया गया।

मिलता है सस्ता

बयान में कहा गया है कि यह ईंधन मानव रहित विमानों और उड़ान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले पिस्टन-इंजन विमानों को ऊर्जा देता है। यह एक उच्च-ऑक्टेन विमान ईंधन है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और गुणवत्ता मानकों के साथ उत्पाद विनिर्देशों को पूरा करता है। साथ ही यह आयातित ग्रेड की तुलना में सस्ता पड़ता है।

देश को होगा फायदा

कंपनी के बयान में आईओसी के चेयरमैन एसएम वैद्य के हवाले से कहा गया है, 'इस विमान गैस का नाम एवी गैस 100 एलएल है और देश में इसके उत्पादन से न केवल विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही ये नए पायलट्स के लिए घरेलू उड़ान संस्थानों में प्रशिक्षण को किफायती भी बनाएगा।' उन्होंने कहा कि दक्षिण अमेरिका, एशिया प्रशांत, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इस ईंधन की भारी मांग है। वैद्य ने कहा कि इंडियन ऑयल का लक्ष्य घरेलू मांग को पूरा करने के बाद इस बाजार में पहुंच स्थापित करना है।

वैश्विक बाजार में होगा आईओसी का दबदबा

वैद्य ने कहा, 'ग्लोबल एविएशन गैसोलीन मार्केट 5३ सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से बढ़ने का अनुमान है। भारत में विमानन यातायात भी 7% बढ़ने की संभावना है। बेहतर प्रदर्शन गुणवत्ता मानकों और प्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ इंडियन ऑयल इसमें अच्छी बाजार हिस्सेदारी सुरक्षित करने का लक्ष्य बना रहा है। कंपनी ने कहा कि एवी गैस का उत्पादन वर्तमान में गुजरात में फर्म की रिफाइनरी में किया जा रहा है, जिसकी वार्षिक क्षमता प्रति माह 5,000 टन ईंधन बाहर निकालने की है।

पुतिन ने मोहम्मद बिन सलमान से की फोन पर बात, ओपेक प्लस बैठक से पहले अहम चर्चा

मॉस्को। एजेंसी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ टेलीफोन पर बातचीत। रूसी राष्ट्रपति की वेबसाइट के अनुसार ओपेक प्लस समूह के सहयोग पर चर्चा की। वेबसाइट ने कहा, राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विकास के साथ-साथ वैश्विक तेल बाजार की स्थिरता प्रदान करने के लिए ओपेक प्लस समूह के भीतर सहयोग पर चर्चा की गई।

रूस के नेतृत्व में होगी ओपेक की बैठक

रूस के नेतृत्व में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और उसके सहयोगियों की बैठक इस सप्ताह होने वाली है। वैश्विक सदस्य तेल की कीमतों और नीतियों पर समन्वय और स्थिरता की तलाश करेंगे। फॉक्स न्यूज के अनुसार, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और ब्रेंट क्रूड सोमवार दोपहर ईटी में 1 फीसदी से ज्यादा नीचे थे।

रूसी तेल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध

यूरोपीय संघ के प्रतिबंध और यूक्रेन पर उसके आक्रमण के बाद लगाए गए जी-7 मूल्य कैप के बावजूद मजबूत रूसी आपूर्ति के संकेत पर तेल दबाव में है। यूरोपीय संघ ने 5 फरवरी से रूसी तेल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यूयॉर्क में ओआंडा के एक वरिष्ठ बाजार विश्लेषक एडवर्ड मोया ने फॉक्स बिजनेस को बताया कि ओपेक उत्पादन कम कर रहा है, और इस बैठक से कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। मोया ने कहा कि समिति चीन की वसूली और रूसी आपूर्ति पर प्रतिबंधों के प्रभाव को देखना चाहती है। क्राउन प्रिंस के साथ राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत यह सुझाव दे सकती है कि सउदी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि रूस उत्पादन को स्थिर रखने के लिए तैयार है। चीनी मांग में वृद्धि की उम्मीद ने 2023 में तेल को बढ़ावा दिया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े कच्चे आयातक ने खपत में सुधार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिज्ञा की है।

बीना रिफाइनरी बल्क ड्रग पार्क को देगी क्रूड, मेडिसिन सॉल्ट बनने से विदशों पर निर्भरता कम हो जाएगी

लखनऊ। एजेंसी

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र सैदपुर की भूमि पर बल्क ड्रग पार्क बनाने को लेकर निवेशकों की सहमति में बीना रिफाइनरी का अहम योगदान रहा है। दवाइयों के साल्ट बनाने वाली कंपनियों को इस रिफाइनरी से क्रूड आयल आसानी से मिल सकेगा। दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला सॉल्ट देश में बहुत कम जगहों पर बनाया जाता है। जरूरत के हिसाब से उत्पादन कम होने के कारण विदेशों पर इसकी निर्भरता रहती है। बहुत सी कंपनियां चीन सहित विभिन्न देशों से सॉल्ट आयात करके विभिन्न दवाइयों का निर्माण करती हैं। इस निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार को बल्क ड्रग पार्क की जरूरत काफी दिनों से महसूस हो रही थी। इसके लिए एक साथ दो हजार एकड़

जमीन, बिजली, पानी, सड़क रेल व हवाई परिवहन, पर्यावरण पहली जरूरत थी। एक साथ इन खूबियों वाले स्थान के आस पास रिफाइनरी का होना सर्वोत्तम स्थिति मानी गयी थी। राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र सैदपुर इन सभी जरूरतों पर फिट बैठ गया।

दवा कंपनियों के लिए प्रस्तावित 25 से 35 एमएलडी पानी यहां से निकलने वाली जामनी बांध की नहर से मिलेगा। सड़क यातायात दुरुस्त करने के लिए उच्चस्तरीय सड़क निर्माण में भी कोई बाधा नहीं है। इसके अलावा यहां से मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी महज नब्बे किलोमीटर दूर है। दवाइयों के सॉल्ट बनाने में क्रूड की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे विभिन्न रासायनिक पदार्थों का रिएक्शन करवाकर साल्ट बनाए जाते हैं। इसलिए बल्क ड्रग पार्क में निवेश करने वाली कंपनियों को क्रूड की प्रचुर मात्रा में इस रिफाइनरी से पूरी होगी। बीना रिफाइनरी का नजदीक होना सैदपुर में बल्क ड्रग पार्क पर निवेशकों की सहमति का प्रमुख कारण बना।

गुगली इंडिया: भारत का पहला गेमिंग प्लेटफॉर्म, जो आपको शानदार गेमिंग का अनुभव प्रदान करेगा!

गेमिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्लेटफॉर्म गुगली भारत में गेमर्स के सबसे बड़े समुदाय का निर्माण करेगा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के अपने मल्टी-गेमिंग प्लेटफॉर्म, गुगली का लॉन्च गेमिंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आया है। यह हर तरह की गेमिंग के लिए भारत का अपना प्लेटफॉर्म है, जो सभी जगह उपलब्ध होगा। गुगली का उद्देश्य विभिन्न डिवाईसेज़ पर एडवांस्ड फीचर्स के साथ एक 'मल्टी-गेमिंग प्लेटफॉर्म' का निर्माण करना है, जहाँ कैज़्युअल और ईस्पोर्ट्स प्लेयर्स आकर भारत में गेमर्स का सबसे बड़ा समुदाय बना सकें। भारत में कैज़्युअल गेमर्स और ई-स्पोर्ट्सप्रेमियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, और आज देश में 400 मिलियन से ज्यादा गेमर्स तथा 2.6बिलियन डॉलर्स से ज्यादा बड़ा गेमिंग बाजार है। लेकिन फिर भी देश में ऐसे संरचनाबद्ध प्लेटफॉर्म की कमी है, जो गेमिंग का बेहतरीन अनुभव प्रदान कर हर तरह के गेमर की जरूरतों को पूरा कर सके। इस कमी को पूरा करने के लिए टेक्नॉलॉजी, गेमिंग, मार्केटिंग, और ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्रों से दिग्गजों की एक टीम ने साल 2021 में भारत का पहला मल्टी-गेमिंग प्लेटफॉर्म, गुगली बनाने का सफर शुरू किया। इसके बाद गुगली ने एक मल्टी-फीचर सेट प्लेटफॉर्म बनाया, जो इसके यूज़र्स को अपने कस्टम टूर्नामेंट बनाने का अवसर देता है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं या फिर इस प्लेटफॉर्म पर अन्य यूज़र्स के टूर्नामेंट में शामिल हो सकते हैं। वो नए दोस्त बना सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, गेमिंग की दुनिया में लेटेस्ट घटनाक्रम से अवगत रह सकते हैं, और गुगली शॉप द्वारा अपने पसंदीदा इन-गेम एस्सेट खरीद सकते हैं। गुगली के लॉन्च के बारे में श्री शुभोदीप पाल, को-फाउंडर एवं सीईओ ने कहा, "हमें खुशी है कि भारतीय गेमर्स गुगली द्वारा गेमिंग का अद्वितीय अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हम गेमिंग को जनसमूह तक पहुँचाना और सभी लोगों को उपलब्ध कराना चाहते हैं। गुगली न केवल गेमर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने में का अवसर देता है बल्कि उन्हें अपना खुद का समुदाय बनाने और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए कस्टम टूर्नामेंट्स की मेजबानी करने में भी समर्थ बनाता है। हमारा प्लेटफॉर्म गेमिंग की हर जरूरत के लिए एक वन-स्टॉप समाधान है। इसके मल्टी-फीचर सेट एक ही सदस्यता के अंतर्गत उपलब्ध हैं। गुगली में हमें भारत को एक ऐसा मंच प्रदान करने पर गर्व है, जो देश में गेमिंग के अनुभव में क्रांति ले आएगा और भारत में गेमिंग का सबसे बड़ा समुदाय बन जाएगा।'

मध्य भारत का सबसे बडा – इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपों 2023 10- 13 फरवरी 2023 तक इंदौर में

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजना के अन्तर्गत प्रदेश में औद्योगिक विकास का रोडमेप तैयार किया गया है जिससे कई औद्योगिक समूह प्रदेश में उद्योग स्थापना हेतु अपना रूख कर रहे है और मालवांचल औद्योगिक दृष्टि से निरंतर विकसीत हो रहा है। इंदौर में 450 एकड़ में मेगा फर्नीचर क्लस्टर, खिलौना क्लस्टर एवं अन्य क्लस्टर की कार्यवाही गतिशील है। कई दवा निर्माण कम्पनियों इंदौर एवं मालवा क्षेत्र में निवेश के लिए आने को तत्पर है। इंदौर में अन्तराष्ट्रीय कार्गो डिपो तथा लाजिस्टिक्स पार्क उद्योगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोगी हो रहा है तथा आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत तीव्रता से अग्रसर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं जनप्रतिनिधियों, प्रशासन व उद्योग विभाग के समन्वय से विकास कार्यों को गति मिल रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के औद्योगिक विकास व यहां के उद्यमियों को एक उन्नत तकनीकी का प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश, फ्युचर कम्युनिकेशन एवं इंडियन प्लास्टपैक फोरम के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 10 से 13 फरवरी 2023 तक स्थानीय लाभगंगा एक्झीबिशन सेन्टर में इंडस्ट्रीयल

इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 का आयोजन किया जा रहा है जिसका विधिवत शुभारंभ 10 फरवरी 2023 को लाभगंगा एग्झीबिशन सेन्टर पर होगा।

इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़े मैन्यूफैक्चरिंग इकाईयां, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स आदि के लिए लाभदायक होगा जहां इंदौर सहित एक्सपों में सम्मिलित होने वाले उद्योगपति और निर्माता उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियों से संवाद कर सकेगें। इस मेगा इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपों में इस वर्ष लगभग 300 स्टॉलो के माध्यम से इंजीनियरिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कम्पोनेंट, कृषि संयंत्रों, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक आदि उत्पादों एवं मशीनरी का प्रदर्शन किया जायेगा।

प्रदर्शनी में प्रमुख कंपनीया हेवल्स, जेनेटिक्स, सिमेन्स, पॉलिकेब, एटलस कॉपको. उएम. डेल्टा, ओमरान आटोमेशन आदि जैसे बड़े कॉरपोरेट शिरकत कर रहे है। इस चार दिवसीय प्रदर्शनी में विभिन्न उन्नत तकनीकी का आदान प्रदान होगा इससे यहां के उद्यमियों को नवीनतम जानकारियों का लाभ मिलेगा साथ ही इंजीनियरिंग एक्सपों 2023 के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़े मैन्यूफैक्चरिंग इकाईयां सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स आदि अनेक सम्मिलित होने वाले उद्योगपति और निर्माता उद्योग एवं व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति एक दूसरे से सीधा संवाद कर सकेगें प्रदर्शनी में वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सपोर्ट रेडीनेस और स्मारिका विमोचन आदि कार्यक्रम भी रहेगें। प्रदर्शनी में विजिटर्स के लिए प्रवेश निशुल्क रखा गया है ताकि अधिक से अधिक उद्योगपतिगण एवं इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकें साथ ही नई तकनीकी की जानकारी लेकर अपने उद्योगों में इसको अपना सके।

इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम

लाभगंगा सेंटर पर श्री रोहन सक्सेना, कार्यपालन निदेशक, एमपीआईडीसी, इंदौर के मुख्य आतिथ्य और एआईएमपी के अध्यक्ष श्री योगेश मेहता, प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल के उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रति वर्ष यह प्रदर्शनी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश, इंडियन प्लास्टपेक फोरम एवं फ्यूचर कम्यूनिकेशन के संयुक्त तत्वावधान में इंदौर के लाभगंगा सेंटर पर आयोजित की जाती है जिसका यह 11वा वर्ष है। इस साल यह मध्य भारत की सबसे बडी एमएसएमई प्रदर्शनी इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 का आयोजन दिनांक 10 से 13 फरवरी 2023 तक लाभगंगा एग्जिबिशन सेंटर बायपास रोड पर आयोजित किया जा रहा है। जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों की बड़ी कंपनिया आ रही हैं। आज सम्पन्न भूमि पूजन अवसर पर श्री रोहन सक्सेना से इंदौर में नवीन कन्वेंशन सेंटर और क्लस्टर विकास संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई जहा एआईएमपी के श्री प्रकाश जैन, श्री दिलीप देव, श्री तरुण व्यास, पूर्व अध्यक्ष श्री प्रमोद डफरिया, श्री हरीश नागर, श्री प्रमोद जैन, श्री राम किशोर राठी, श्री मनीष चौधरी, श्री गिरीश पंजाबी, श्री अजय सिंह दासुंदी, श्री सुरेन्द्र देवरा, श्री अमेय गोखले, श्री लक्ष्मण दुबे, श्री अनिल चतुर्वेदी आदि अन्य मौजूद रहे।

कोरोना वायरस से जुड़ी मौतों को 90% तक कम कर सकते हैं, नई स्टडी में सामने आया उपाय

नई दिल्ली। एजेंसी

कोविड महामारी का खतरा अभी भी बना हुआ है और दुनिया के कुछ देशों में तो हालात चिंताजनक हैं. ऐसे में एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि पहली दो खुराक की तुलना में तीसरी बूस्टर डोज के जरिए कोरोना वायरस से जुड़ी मौतों को 90% तक कम कर सकते हैं। यहां तक कि जिनको हेल्थ इश्युज हैं, उन्हें भी बचाया जा सकता है। अध्ययन हांगकांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा आयोजित किया गया है और यह कनाडाई मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

हांग कांग विश्वविद्यालय के एस्तेर चैन ने कहा, 'हमने मल्टीमॉर्बिडिटी वाले वयस्कों में COVID-19 से संबंधित मौत का जोखिम काफी हद तक कम पाया, जिन्हें BNT162b2, एक mRNA वैक्सीन, या कोरोनावैक, एक निष्क्रिय संपूर्ण-वायरस वैक्सीन की होमोलॉगस बूस्टर खुराक मिली।' चैन ने कहा, 'ये परिणाम ओमिक्रॉन महामारी के बीच मल्टीमॉर्बिडिटी वाले लोगों में मृत्यु दर को कम करने में दो अलग-अलग तकनीकी प्लेटफार्मों के टीकों की बूस्टर खुराक की प्रभावशीलता का समर्थन करते हैं।

अलग-अलग समुदाय के लोग जुड़े हुए रहते हैं

लेखक और हांगकांग विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक सैड फ्रांसिस्को लाइ कहते हैं कि हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि इस समय पर, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय ने महामारी के बीच मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से अलग-अलग समुदाय के लोगों के बीच इसका अध्ययन किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार बूस्टर टीकाकरण से संभावित लाभ को उजागर करते हैं, विशेष रूप से बहुमूत्रता के साथ रहने वाली कमजोर आबादी में, और पहले बूस्टर से परे SARS-CoV-2 टीकों के भविष्य के बूस्टर खुराक के लिए पुराने लोगों और पुरानी स्थिति वाले लोगों पर हाल के फोकस का समर्थन करते हैं।

एविएशन फ्यूल प्राइस 4 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में मजबूती के चलते देश में विमान ईंधन के दामों में बुधवार को चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार दसवें महीने कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों की मूल्य अधिसूचना में बताया गया कि एटीएफ के दाम में 4,218 प्रति किलोलीटर या 3.9 फीसदी की वृद्धि की गई है जिससे राष्ट्रीय राजधानी में इसके दाम 1,12,356.77 प्रति किलोलीटर हो गए हैं। इससे पहले, नवंबर से एफटीएफ के दाम तीन बार घटाए गए थे। एक जनवरी को इसके दाम 1,17,587.64 प्रति किलोलीटर से घटाकर 1,08,138.77 प्रति किलोलीटर किए गए थे। एक दिसंबर को दामों में 2.3 फीसदी की और एक नवंबर को इनमें 4.19 फीसदी की कटौती की गई थी। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार दसवें महीने अपरिवर्तित हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की 89.62 रुपये प्रति लीटर है। वाणिज्यिक एलपीजी के दाम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,769 रुपये है। वहीं घरेलू रसोई गैस के 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 1,053 रुपये का है।

निर्मला के बजट में मिडिल क्लास, महिला, वेतनभोगियों के लिए बल्ले-बल्ले

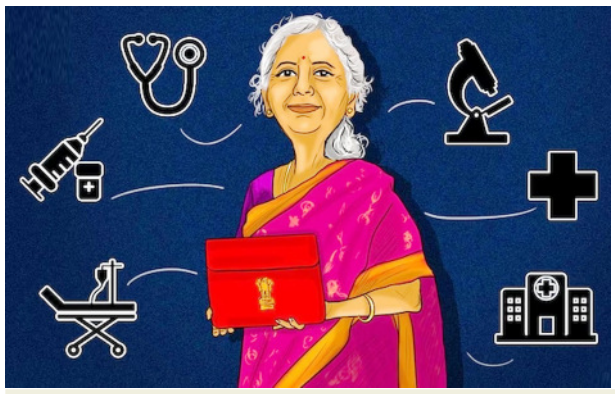

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पांचवां बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने अनुमान के मुताबिक इसबार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया है। नई टैक्स व्यवस्था में में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है।

पुरानी टैक्स व्यस्था

3-6 लाख- 5% टैक्स
6-9 लाख- 10% टैक्स
12-15 लाख- 20% टैक्स
15 लाख से ऊपर- 30% टैक्स

7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं

वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी है। लेकिन ये नए टैक्स व्यवस्था के लिए 7 लाख छूट की सीमा लागू होगी। पुराने टैक्स व्यवस्था में कर छूट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। नए टैक्स सिस्टम में टैक्स स्लैब 7 से घटाकर 5 किया गया।

महिला सम्मान सेविंग पत्र

वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान सेविंग पत्र की घोषणा की। इस योजना के तहत दो साल के लिए 2025 तक के लिए निवेश किया जाएगा। इसके तहत महिला, लड़की के लिए दो साल के लिए राशि फिक्स करने की योजना होगी। इसपर फिक्स 7.5 फीसदी ब्याज दर होगी और इसमें पार्शियल राशि निकालने की भी सुविधा होगी।

पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी।

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए राशि

वित्त मंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए उनकी सरकार बड़ी राशि खर्च करेगी। पुराने वाहनों को हटाने हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। हम पुराने गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए राशि का आवंटन करेंगे। इसके तहत पुराने एंबुलेंस को भी स्क्रैप किया जाएगा।

बजट के कुछ बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं। केवाईसी की प्रक्रिया आसान की जाएगी। डिजिलॉकर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। पहचान पत्र के तौर पर पैन मान्य होगा। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया को शुरू की जाएगी। ग्रीन ग्रोथ पर भी सरकार का जोर। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण के अनुसार लाइफस्टाइल पर जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2070 तक भारत इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

वित्त मंत्री ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए मेक AI इन इंडिया को बढ़ावा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे। यहां AI को बढ़ावा देने के लिए खोज से लेकर तमाम तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।

रेलवे को बड़ा बूस्ट

वित्त मंत्री निर्मला ने रेलवे को बड़ा बूस्ट दिया है। उन्होंने रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का खर्च। रेलवे में 100 अहम योजनाओं की पहचान की गई है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है। रेलवे क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रयास।

पीएम आवास योजना का खर्च बढ़ाया गया

निर्मला ने ऐलान किया कि पीएम आवास योजना का खर्च 66 फीसदी बढ़ाया गया है। इसके लिए 79 हजार करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। पूंजीगत निवेश बढ़कर 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इंफ्रा पर खर्च बढ़कर 10 लाख करोड़ पहुंच गया है।

जेल में बंद गरीबों की जमानत के लिए सरकार देगी पैसा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले एक साल तक 80 करोड़ गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। इसपर 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा। जेल में बंद गरीबों की जमानत के लिए सरकार देगी पैसा। कृषि क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का लक्ष्य रखा गया है।

2027 तक एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 2047 तक बच्चों में खून की कमी को दूर करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि अब मेनहोल साफ करने के लिए उसके अंदर आदमी नहीं उतरेंगे। शहरों में सफाई योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी।

न्यू फॉर्मा प्रोग्राम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में फॉर्मास्युटिकल को बढ़ावा देने के लिए न्यू फॉर्मा प्रोग्राम बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के लिए लैब की व्यवस्था की जाएगी। मेडिकल उपकरण बनाने वाले कोर्स शुरू किए जाएंगे।

सप्तऋषि योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सप्तऋषि योजना का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की अहम योजना का भी जिक्र किया। इसके तहत

इन्क्लूसिव डिवेलपमेंट- किसानों, महिला, युवा, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। वंचितों को वरीयता दी जाएगी

डिजिटल इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर- इसके जरिए किसानों के समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश की जाएगी। इसके अलावा फसल, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक उद्योग और स्टार्टअप के लिए मदद। एग्रीकल्चर एक्सलेटर फंड बनाया जाएगा। एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जिससे लाभ के मौके बने।

मोटे अनाज उगाने के मोर्चे पर भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री अन्न को भारत को बड़ा हब बनाने की कोशिश की जा रही है।

रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर काम

रोजगार के सृजन के लिए और छोटे उद्योग को मजबूत करने के लिए सरकार काफी कदम उठा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को जबरदस्त सफलता मिली है। महिलाओं के प्रोडक्ट को बाजार में पहुंचाने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। हरित तकनीक और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन योजनाओं से एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को काफी मजबूती मिल रही है।

प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी

निर्मला ने कहा कि बजट में सभी जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखा गया है। 80 करोड़ लोगों को अनाज केंद्र सरकार दे रही है। वसुधैव कटुंबमकम थीम के जरिए आम लोगों के लिए एजेंडा तय करके हम स्थायी विकास की कोशिश में जुटे हैं। प्रति व्यक्ति आय देश में बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। पिछले 9 साल में हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं।

भारत का भविष्य सुनहरा है

मैं 2023-2024 का बजट पेश कर रही हूं। इस बजट के जरिए हम आगे का बुनियाद को मजबूत करेंगे। इस बजट के लिए एक संपन्न भारत को बनाएंगे। युवा, महिला, किसान, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ये बजट काफी अहम होगा। आजादी के 75 वें साल में दुनिया में भारत को चमकता सितारा कहा है। हमारी ग्रोथ रेट काफी शानदार रही है। दुनिया के कई बड़ी अर्थव्यवस्था से हमारी इकॉनमी काफी अच्छी है। हमारा भविष्य काफी सुनहरा है।

पांचवीं बार बजट पेश कर रही हैं निर्मला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांचवीं बार बजट पेश कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल बजट सत्र से पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री जनता और दुनिया की उम्मीदों को पूरा करेंगी। पीएम के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिल सकती है। पिछली बार निर्मला ने डेढ़ घंटे का बजट भाषण दिया था।

मोदी राज 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट

2024 के आम चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। यानी 17वीं लोकसभा का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। मोदी कैबिनेट ने निर्मला के बजट को भी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करेंगी।

बजट में क्या महंगा क्या सस्ता

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्तमान में उएऊ के टैक्स स्लैब में चार दरें - 5%, 12%, 18% और 28% हैं। आवश्यक वस्तुओं को इस टैक्स से छूट है या सबसे निचले स्लैब में रखा है। GST से जुड़े सभी फैसले उएऊ काउंसिल लेती है।

अब नजर बीते एक साल पर...

बीते साल आटा 23% बढ़ा तो लोन भी महंगा हो गया है। पिछले साल जनवरी में एक किलो आटा 26 रुपए में मिलता था। दिसंबर में तो इसकी कीमत बढ़कर 32 रुपए किलो हो गई। इसी तरह हर घर में रोजाना उपयोग होने वाले सामान जैसे तेल, दूध और चावल जैसी चीजों के दाम भी बढ़े हैं। 2022 में पहली बार घरेलू गैस सिलेंडर 1,000 रुपए के पार निकल गया। RBI की ओर से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बढ़ाई गई ब्याज दरों के कारण लोन भी महंगे हो गए हैं। नीचे दिए ग्राफिक्स से आप बीते एक साल की महंगाई को समझ सकते हैं...

टॉप 5 इकोनॉमी में महंगाई

केवल भारत ही नहीं है जो महंगाई का सामना कर रहा है। दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत की बात करें तो दिसंबर 2022 में सबसे ज्यादा 8.6% महंगाई जर्मनी में रही। भारत में दिसंबर में रिटेल महंगाई (CPI) घटकर 5.72% पर आ गई। ये 12 महीनों का निचला स्तर है। यहां खाने-पीने का सामान खास तौर पर सब्जियों की कीमतों के घटने की वजह से महंगाई से कुछ राहत मिली है।

बजट 2023 पर प्रतिक्रिया

गहणियों के लिए सराहनीय बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट इस महंगाई के दौर में एक सराहनीय बजट हू क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए योजनाओं एवं रोजगार का प्रावधान किया गया है। समय के अनुसार हेल्थ केयर के लिए बजट बढ़ाया गया है वह बहुत ही आवश्यक था। यह बजट आने वाले साल में स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी करेगा ऐसी उम्मीद है।

-श्रीमती उन्नति वाधवानी
(एडवोकेट)

बजट पर प्रतिक्रिया

नए भारत का दूरदर्शी बजट

इंदौर। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के महानगर मीडिया प्रभारी संतोष वाधवानी में केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला बजट बताया। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रत्न विशेषज्ञ संतोष वाधवानी ने कहा कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट है।

बजट देश में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला बजट है, जो नए भारत की नींव रखेगा । ये बजट, एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा।

-संतोष वाधवानी व्यापारी प्रकोष्ठ
भारतीय जनता पार्टी महानगर इंदौर

सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की यात्रा को सुगम बनाने के लिए

विकासोन्मुखी, दीर्घ अवधि, रोजगार केंद्रित बजट: फियो अध्यक्ष, डॉ. ए शक्तिवेल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए फियो अध्यक्ष डॉ. ए शक्तिवेल ने कहा कि बजट में देश को सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसाकि अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का अनुमान है, बनी रहने में सहायता करने के लिए बजट में निवेश और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था की विकास संभावना पर फोकस किया गया है। डॉ. ए शक्तिवेल ने कहा कि सीमा शुल्क में कई बदलाव आयात प्रतिस्थापन के प्रयास के अतिरिक्त विनिर्माण और निर्यातों को प्रतिस्पर्धा प्रदान करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश परिव्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि सहित 10 लाख करोड़ तक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण, रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजी, परिव्यय, बंदरगाह, कोयला, स्टील, उर्वरक में 100 अवसंरचना परियोजनाएं तथा टियर-2 एवं 3 शहरों में शहरी अवसंरचना विकास फंड के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे सहित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलों का अर्थव्यवस्था और रोजगार पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पडेगा।

व्यक्तिगत आयकर में तेज कटौती तथा बचत को प्रोत्साहन से क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे आवासन सहित मांग में बढोतरी होगी और इससे हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में और अधिक अनुकूल बनेगी। बजट में 3400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर अपराधीकरण में परिवर्तित करने और 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करके बड़ी संख्या में अनुपालनों को हटाने के जरिये व्यवसाय करने की सुगमता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डीनेचर्ड इथिल अल्कोहल तथा कच्चे ग्लिसरीन पर शुल्क में कमी से रसायन क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं को सहायता मिलेगी, झींगा आहार के उत्पादन के लिए प्रमुख इनपुट पर शुल्क में कमी से समुद्री निर्यात में मदद मिलेगी। इसी प्रकार प्रयोगशाला में विकसित हीरे के निर्माण के लिए बीजों पर शुल्क में कमी और रत्न एवं आभूषण निर्यातों को सुगम बनाने के लिए प्रदान किए गए अनुसंधान एवं विकास अनुदान से भी अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा।

एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पादों तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के संवर्धन और बिक्री के लिए राज्यों में यूनिटी मॉल की स्थापना से कारीगरों, शिल्पकारों तथा किसानों के लाभ के लिए ऐसे उत्पादों को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। डॉ. शक्तिवेल ने कहा कि हमें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी ऐसे स्टोर्स लगाने की आवश्यकता है जिससे कि ऐसे उत्पादों की वैश्विक दृश्यता को भी प्रोत्साहित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्ट अप्स तथा नवोन्मेषकों के लिए एग्री एक्सीलरेटर फंड के लांच, भारतीय मिलेट संस्थानों की स्थापना तथा कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्पेशल विंडो की सराहना करते हुए, फियो अध्यक्ष ने कहा कि आपूर्ति पक्ष बाधाओं एवं लॉजिस्टिक्स चुनौतियों को देखते हुए एक नए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) योजना के साथ इसकी सहायता करने की आवश्यकता है। फियो प्रमुख का मानना है कि ब्याज समकरण स्कीम के लिए आवंटन में 2022-23 के 2376 करोड़ रुपये की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक 2932 करोड़ रुपये के आवंटन से विशेष रूप से एमएसएमई द्वारा निर्यात के समर्थन में सहायता प्राप्त होगी और इसका परिणाम सबवेंशन सहायता में वृद्धि के रूप में सामने आएगा जैसाकि बढ़ती ब्याज दरों को देखते हुए निर्यातकों द्वारा मांग की गई है। डॉ. शक्तिवेल ने कहा कि जहां एमएआई स्कीम के लिए आवंटन में 2022-23 के 160 करोड रुपये से बढाक़र 2023-24 में 200 करोड़ रुपये किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन यह पर्याप्त नहीं भी हो सकता है क्योंकि वैश्विक व्यापार प्रदर्शनियां निरंतर शोकेसिंग के अवसर प्रदान कर रही हैं जिनका दोहन किए जाने की आवश्यकता है। उन्होने दुहराया कि आक्रामक विदेशी विपणन के लिए एक योजनाबद्ध स्कीम को एक बड़े कौर्पस के साथ अधिसूचित किया जा सकता है जिससे कि निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

सरकार की इनकम कम, खर्चा ज्यादा... लेना पड़ेगा रेकॉर्ड 15.4 लाख करोड़ रुपये का कर्जा

नई दिल्ली । एजेंसी

केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में रेकॉर्ड 15.4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। सरकार ने बजट में यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार खर्च और इनकम के बीच के अंतर को पाटने के लिए यह कर्ज लेगी। बजट में बताया गया कि सरकार अगले वित्त वर्ष में डेटेड सिक्युरिटीज सहित दूसरे स्रोतों से रिकॉर्ड 15.4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बना रही है। यह 31 मार्च, 2023 को खत्म हो रहे चालू वित्त वर्ष में लिए गए कुल कर्ज 14.21 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी।

राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए लेना पड़ेगा कर्ज

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए डेटेड सिक्युरिटीज से शुद्ध बाजार कर्ज 11.8 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा, 'शेष वित्तपोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से होने की उम्मीद है। इसके साथ कुल बाजार कर्ज 15.4 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।'

27 जनवरी तक जुटाए 12.93 लाख करोड़ रुपये

सरकार ने 27 जनवरी तक 12.93 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल कर्ज लक्ष्य 14.21 लाख करोड़ का 91 फीसदी है। केंद्र और राज्यों पर संयुक्त रूप से कर्ज सकल घरेलू उत्पाद (उ्ञ्ज) के 83 फीसदी के बराबर है। वित्त मंत्री ने सब्सिडी बिल में वृद्धि के बावजूद राजकोषीय घाटा लक्ष्य 6.4 फीसदी पर बरकरार रखा है। उन्होंने कहा, 'वित्त वर्ष 2023-24 में कर्ज के अलावा कुल आय 27.2 लाख करोड़ रुपये और कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपये है। कुल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।'

जीडीपी का 5.9% है राजकोषीय घाटे का टार्गेट

वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रखा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए डेटेड सिक्युरिटीज से सकल कर्ज 14,95,000 करोड़ रुपये आंका था। हालांकि, सरकार ने पिछले साल सितंबर में सकल कर्ज को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए घटाकर 14.21 लाख करोड़ करने की घोषणा कर दी थी। 2021-22 के लिए सकल कर्ज 12,05,500 करोड़ रुपये था।

बजट के बाद शेयर बाजार: सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 59,708 पर बंद, निफ्टी 45 अंक गिरा, अडाणी एंटरप्राइजेज 26% टूटा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। ऐसे में बाजार की नजर सरकार की घोषणाओं पर रही। भारतीय बाजार आज ऊपर खुले। बजट भाषण के बाद सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी देखी गई। हालांकि बाद में ये केवल 158 अंक की तेजी के साथ 59,708 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 45 अंक गिरकर 17,616 पर बंद हुआ। बजट के दिन बीते सालों में बाजार के एक्शन की बात करें तो बीते 7 सालों में औसतन 0.9% का पॉजिटिव मूवमेंट आया है। 2021 में बजट के दिन बाजार में 5% की तेजी आई थी।

बजट 2023 पर प्रतिक्रिया

मध्यमवर्गीय के लिए आयकर स्लैब प्राणवायु का काम करेगा

वित्त मंत्री द्वारा इस वर्ष आयकर सीमा 7 लाख कर देने से मध्यमवर्गीय परिवारों को अत्यंत ही राहत का सामना करना पड़ेगा और नया आयकर स्लैब प्राणवायु का काम करेगा। नौकरी पेशा वाले मिडिल क्लास लोग इस बजट से पूरे वर्ष लाभान्वित होंगे और यह बजट सही मायनों में आम बजट के नाम को चरितार्थ कर रहा है। जनता की उम्मीदों पर यह बजट पूरी तरीके से खरा उतरेगा।

-योगेश द्विवेदी (एडवोकेट एवं कर सलाहकार)

गरीब और मध्यम वर्ग के नाम है ये बजट (रक्षा बजट का अधिकांश भाग घरेलू बाजार से क्रय करना इस बजट का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष)

एडवोकेट एवं विधि व्याख्याता पंकज वाधवानी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट गरीब और मध्यम वर्ग को को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। जिस प्रकार से पहली बार इस केंद्रीय बजट में रक्षा बजट का अधिकांश भाग घरेलू उत्पादों से क्रय करने का कहा गया है यह क्रांतिकारी कदम है और यही बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को केंद्रीय बजट के लिए साधुवाद -वाधवानी

भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के नगर मीडिया प्रभारी संतोष वाधवानी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने लिए उठाया गया कदम बताया है वही वाधवानी ने यह भी कहा कि देश के सभी व्यापारियों की ओर से बजट का स्वागत करते हुए बजट को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर रोजगार देने वाला बजट बताया श्री वाधवानी ने यह भी कहा कि इन सभी प्रावधानों से देश के विकास और आत्मनिर्भरता को एक नई उड़ान मिलेगी बजट के फल स्वरूप रूप इसके परिणाम सुखद व व्यापारियों को लाभान्वित करेंगे उन्होंने वित्त मंत्री को साधुवाद पत्र भी भेजा है।

घर पर मौजूद इन पांच वास्तु दोषों के कारण आती हैं परेशानी, आज ही दूर करें

श्री रघुनंदन जी
9009369396
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद
अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट

प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पंसदीदा जगह उनका अपना घर लगता है। दिनभर काम के सिलसिले में बाहर रहने के बाद जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसको सबसे ज्यादा सुकून अपने घर पर ही मिलता है। लेकिन घर वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है या फिर घर बनाने के बाद वास्तु नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस घर में सुकून नहीं अशांति महसूस होने लगती है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि किसी के घर में छोटी-बड़ी बात को लेकर विवाद होता रहता है या फिर घर के सदस्य बीमार रहते हैं। अचानक धन की समस्या आने लगती है। काम बिगड़ने लगते हैं। बेवजह लड़ाई होती हैं। इन सबका कारण घर पर मौजूद वास्तुदोष हो सकता है। आइए जानते हैं घर पर मौजूद 5 ऐसे वास्तु दोषों के बारे में जिन्हें जल्द दूर कर लेना चाहिए।

वास्तु दोष के 5 कारण

1.वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का मुख्य दरवाजा घर के अन्य दरवाजों की तुलना में छोटा होना अशुभ माना जाता है। मुख्य दरवाजा सभी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं होने पर उस घर में हमेशा पैसों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।

2.यदि आपके घर के बेडरूम में वॉश बेसिन लगा हुआ है तो यह वास्तु दोष का कारण बनता है, जो आपके वैवाहिक जीवन में कई प्रकार के परेशानियों का कारण बनता है। वास्तु नियम के अनुसार घर के किसी भी बेडरूम में वॉश बेसिन नहीं होना चाहिए।

3.यदि आपके घर में बाथरूम या वॉश बेसिन के नल से पानी लीक हो रहा है, तो यह वास्तु दोष का एक मुख्य कारण है। ऐसा होना से घर में कई प्रकार की परेशनियां बेवजह जन्म लेने लगती हैं।

4.यदि आपके घर के आस-पास कोई सूखा पेड़ या बिजली का खंभा है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। यह भी वास्तु दोष का कारण बनता है और घर में आर्थिक परेशानियां आती हैं।

5.आपके घर में टूटा कांच और बिखरा हुआ सामान नेगेटिव एनर्जी फैलती है इससे परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है।

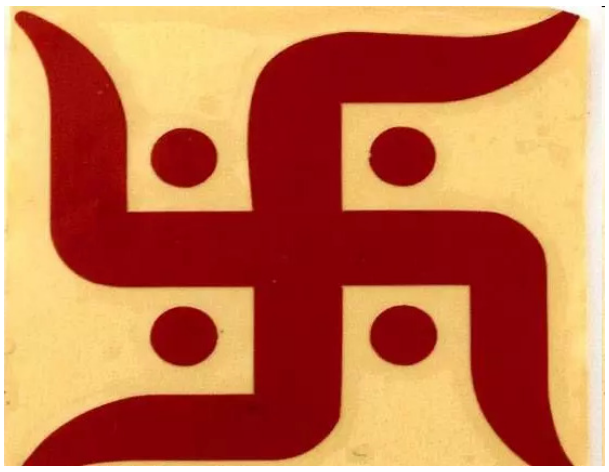

क्यों माना जाता है स्वस्तिक चिह्न अत्यंत शुभ? जानिए क्या है कारण

आचार्य संतोष भार्गव
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

सनातन धर्म में स्वस्तिक चिह्न को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी बड़े अनुष्ठान या हवन से पहले स्वस्तिक चिह्न निश्चितरूप से बनाया जाता है। यह चिह्न न केवल शुभता का प्रतीक है, बल्कि इसे बनाने से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता। इसके साथ ही इससे देवी-देवता भी होते हैं। मान्यताओं के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिह्न बनाने से व्यक्ति के जीवन में और परिवार सुख-समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, स्वस्तिक चिह्न से सभी मांगलिक कार्य सिद्ध होते हैं। आइए जानते हैं, क्यों स्वस्तिक चिह्न को माना जाता है अत्यंत शुभ।

स्वस्तिक चिह्न का अर्थ

स्वस्तिक शब्द तीन भिन्न शब्दों के मेल से बना है। 'सु' का अर्थ शुभ है, 'अस' अर्थात अस्तित्व और 'क' का मतलब है कर्ता। इसलिए इस शब्द का पूरा अर्थ है मंगल करने वाला। शास्त्रों में इसे भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पूजा में जिस तरह इन्हें सबसे पहले पूजा जाता है उसी तरह स्वस्तिक को मंगल कार्य शुरू करने से पहले बनाया जाता है।

स्वस्तिक चिह्न का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में स्वस्तिक चिह्न के कई फायदे बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दिवाली के दिन स्वस्तिक चिह्न को तिजोरी पर बनाने से धन की कमी दूर हो जाती है और तिजोरी कभी खाली नहीं रहती है। इसलिए जो लोग नौकरी या व्यापार में घाटा अनुभव कर रहे हैं उन्हें ईशान कोण में लगातार सात गुरुवार सूखी हल्दी से स्वस्तिक का चिह्न बनाना चाहिए। इससे उन्हें सफलता प्राप्त होगी। वास्तु में भी इसके महत्व के विषय में विस्तार से बताया गया है।

बजट का 'सप्तर्षि' स्वरूप नये भारत को सातवें आसमान पर ले जायेगा- डॉ. पुनीत द्विवेदी

डॉ. पुनीत कुमार द्विवेदी
(वित्त विश्लेषक)
प्रोफ़ेसर एवं समूह निदेशक
मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स इंदौर

■'एग्री स्टार्टअप योजना' कृषि नवाचार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।■ युवाओं को कृषि स्टार्टअप्स की ओर अग्रसर करने के लिये प्रयास सर्वोत्तम है। ■ ग्रीन रिवोल्यूशन एवं कृषि वर्धक निधि की स्थापना कल्याणकारी कदम। ■जनजाति क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालयों की स्थापना जनजाति समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करेगी।

नये भारत का नया बजट एक कल्याणकारी बजट सिद्ध होगा। कृषि क्षेत्र में युवाओं को स्टार्टअप के लिये अवसर देना एक अभिनव प्रयोग एवं सराहनीय पहल है जिससे कृषि क्षेत्र में नवीन क्रांति संभव है। युवाओं में कृषि क्षेत्र में अवसर मिलेंगे और बेरोज़गारी की समस्या का भी स्थाई समाधान संभव है। कोरोना महामारी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हुआ और लोगों ने शहरों को छोड़ा। युवा ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपने लिये रोज़गार ढूँढने लगे। कुछ ने तो स्वयं का कृषि आधारित उद्योग आरंभ किया। यह एक विशेष परिवर्तन था जो कि आपदा काल में एक नवीन अवसर के रूप में उभर कर आया। सरकार ने इस पलायन में सम्भावना देखा है। कुशल मानव संसाधन अपने गाँव या आस -पास के क्षेत्रों में ही यदि रोज़गार पा जाता है या व्यवसाय के अवसर ढूँढ लेता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और तेज़ी से बढ़ेगी। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा अटल इन्नोवेशन मिशन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में इंक्युबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। कई ऐसे इंक्युबेटर हैं जो कृषि से संबंधित उद्योगों एवं आईडियाज को परामर्श देने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ तकनीकि सहयोग, सीड फंड आदि के द्वारा एग्री टेक स्टार्टअप्स की मदद करते हैं। कृषि बाहुल्य क्षेत्रों में इस प्रकार के संबंधित इंक्युबेटर की स्थापना की गई है।नवीन बजट के द्वारा इन इंक्युबेशन सेंटर्स को और सुदृढ़ करने का लक्ष्य साधा गया है। फ़ूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी अपार संभावनायें परिलक्षित हो रही हैं। एग्रीकल्चर एक्सिलेरेटर फंड कृषि क्षेत्र में युवाओं के नवाचारों को नयी उर्जा देगी। इस बजट में कृषि के साथ-साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स की भूमिका को तय किया गया है। जिससे कि युवाओं के टूरिज़्म के क्षेत्र में नवाचार करने का मौक़ा मिलेगा और इस क्षेत्र में भी नवाचारों के माध्यम से रोज़गार सृजन का स्वप्न देखा गया है। फ़ार्मा क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिये, चिकित्सा उपकरणों में नवाचार हेतु, बहु-विषय पाठ्यक्रमों का व्यवस्था को सशक्त बनाने, अध्यापकों के समुचित प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था इस बजट को और शक्तिशाली बनाते हैं। सस्ती परंतु उत्कृष्ट शिक्षा को जन-जन तक, दूर दराज के क्षेत्रों (ग्राम, ग्राम पंचायत) तक क्षेत्रीय भाषा में पहुँचाने हेतु 'नैशनल डिजिटल लाईब्रेरी' की स्थापना प्रशंसनीय कदम है। बजट में जनजाति क्षेत्रों की चिंता ने सामान्य जनमानस का हृदय जीत लिया है। जनजाति क्षेत्रों में विशेष एकलव्य स्कूलों की स्थापना, लगभग 39000 शिक्षकों की भर्ती, कुल 15000 करोड़ रूपये का पैकेज जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारेगा जिससे जनजाति क्षेत्र भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकेंगे।

अंततः यह कहना उचित होगा कि नवीन बजट नवाचार केंद्रित बजट है जिसमें शिक्षा, कृषि एवं स्टार्टअप्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास किया गया है, साथ ही साथ रोज़गार सृजन के अवसरों को प्रोत्साहन दिया गया है जो कि स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदमों को दर्शाता है।

सिगरेट के धुएं में उड़ जाता है GDP का एक फीसदी से ज्यादा हिस्सा

वित्त मंत्री ने बढ़ाया टैक्स

नई दिल्ली। एजेंसी

सिगरेट की कश लगाने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश बजट में सिगरेट पर 16 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। भारत उन 182 देशों में शामिल है जिन्होंने तंबाकू पर कंट्रोल करने के लिए WHO के एक फ्रेमवर्क कनवेंशन पर साइन किए हैं। इसके तहत तंबाकू से बने सभी प्रॉडक्ट्स की रिटेल कीमत पर कम से कम 75 फीसदी टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। भारत में सिगरेट पर टैक्स 52.7 फीसदी, बीड़ी पर 22 फीसदी और जर्दा तंबाकू पर 63.8 फीसदी टैक्स लगता है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 15 साल से अधिक उम्र के करीब 27 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉड्यूसर है। जानकारों का कहना है कि तंबाकू से बने आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने और कड़े कानूनों से न केवल लोगों की सेहत में सुधार होगा बल्कि इससे भारत को 2025 तक पांच ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने में भी मदद मिलेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स के हेड प्रोफेसर अरविंद मोहन ने कहा कि तंबाकू से होने वाले हेल्थ समस्याओं से देश की इकॉनमी पर बड़ा बोझ पड़ता है। यह देश की जीडीपी का 1.04 फीसदी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने से सरकारा का खजाना भरेगा।

कोर्ट के फैसले के बाद अब नहीं चलेगी गूगल की मनमानी

स्मार्टफोन यूजर्स चुन पाएंगे डिफॉल्ट सर्च इंजन

नई दिल्ली। एजेंसी

टेक्नॉलजी कंपनी गूगल ने बुधवार को कहा कि वह भारत में एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स को 'डिफॉल्ट' यानी कुछ खोजने पर खुद खुलने वाले सर्च इंजन चुनने के लिए इजाजत देगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के खिलाफ अदालत से कोई राहत नहीं मिलने के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ण्ण्ध के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था। आदेश के तहत गूगल पर अपनी एंड्रॉयड को लेकर दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

60 करोड़ स्मार्टफोन में से 97% में यही सिस्टम

देश में करीब 60 करोड़ स्मार्टफोन में से लगभग 97 प्रतिशत इसी प्रणाली पर चलती है। CCI ने 'प्ले स्टोर' नीतियों से जुड़े मामले में भी अमेरिकी टेक कंपनी पर 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। गूगल ने एक ब्लॉग में लिखा है कि हम भारत में स्थानीय कानून और नियमों को गंभीरता से पालन करने के वचन को दोहराते हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग का एंड्रॉयड और प्ले स्टोर को लेकर हाल का जो निर्देश है, उससे भारत के लिए उल्लेखनीय बदलाव की जरूरत है। आज हमने ण्ण्ध को सूचित किया कि हम कैसे उनके निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

भारतीय यूजर्स को अपने डिफॉल्ट सर्च इंजन के चयन का विकल्प

इन बदलावों में मूल उपकरण मैन्युफैक्चर या स्मार्टफोन बनाने वालों को अपने उपकरणों पर पहले से इंस्टॉलेशन के लिए गूगल के अलग-अलग ऐप को लेकर लाइसेंस लेने की आजादी शामिल है। इसमें कहा गया है कि एंड्रॉयड यूजर्स हमेशा से अपने डिवाइस को अपनी पसंद के अनुसार बदलाव करने में सक्षम रहे हैं। भारतीय यूजर्स को अपने डिफॉल्ट सर्च इंजन के चयन का विकल्प होगा। यह विकल्प जल्दी ही दिखाई देने वाली 'चॉइस स्क्रीन' पर उपलब्ध होगा। जब यूजर्स भारत में नए एंड्रॉयड स्मार्टफोन या टैबलेट को सेट करेंगे, उन्हें यह विकल्प दिखेगा।

एड मार्केट में दबदबा, गूगल पर केस

अमेरिकी न्याय विभाग और आठ राज्यों ने मंगलवार को गूगल के खिलाफ ऑनलाइन विज्ञापन में कथित एकाधिकार को लेकर केस दाखिल किया। मुकदमे में ऑनलाइन विज्ञापन के पूरे सिस्टम पर गूगल के कथित एकाधिकार को तोड़ने की मांग की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इससे विज्ञापनदाताओं, उपभोक्ताओं और यहां तक कि अमेरिकी सरकार को भी नुकसान पहुंच रहा है। सरकार ने शिकायत में आरोप लगाया कि गूगल अधिग्रहण के जरिए ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में प्रतिद्वंद्वियों को 'बेअसर या खत्म' करना चाहता है। गूगल की प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के चलते विज्ञापनदाताओं के लिए दूसरे प्रतियोगियों की पेशकश का उपयोग करना मुश्किल हो रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका में अब बड़ी तकनीकी कंपनियों पर लगाम लगाने की कवायद की जा रही है।

अल्फाबेट ने दिया यह बयान

अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, एकाधिकार से मुक्त और निष्पक्ष बाजारों को नुकसान पहुंचता है, जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था आधारित है। वे नई खोज को रोकते हैं। वे उत्पादकों और श्रमिकों को नुकसान पहुंचाते हैं और वे उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं। वहीं गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक ने एक बयान में कहा कि यह मुकदमा नई खोज को धीमा कर देगा, विज्ञापन शुल्क बढ़ाएगा और हजारों छोटे व्यवसायों और प्रकाशकों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल बना देगा। बता दें कि इस समय गूगल की आमदनी में डिजिटल विज्ञापन की 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

मिल गया ऑस्ट्रेलिया की सांस रोकने वाला जानलेवा रेडियो एक्टिव कैप्सूल, ढूंढना 'भूसे में सुई खोजने' जितना था मुश्किल

पर्थ। एजेंसी

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अधिकारियों ने बुधवार को उस छोटे खतरनाक रेडियोधर्मी कैप्सूल को तलाश लिया जो पिछले माह इस 1,400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर ढुलाई के दौरान ट्रक से गिर गया था। अधिकारी ने कहा कि कैप्सूल को ढूंढना भूसे के ढेर से एक सूई खोजने जैसा था। अधिकारियों ने बताया कि मटर के आकार का यह कैप्सूल न्यूमैन के दक्षिण में ग्रेट नॉर्दर्न हाईवे पर मिला। यह कैप्सूल जानलेवा स्तर तक खतरनाक था और लोगों को इससे दूर रहने की चेतावनी दी गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि इसका पता 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे एक खोजी वाहन द्वारा लगाया गया जब विशेषज्ञ उपकरण ने कैप्सूल से निकलने वाले विकिरण से इसकी पहचान की। आपातकालीन सेवा मंत्री स्टीफन डॉसन ने कहा, 'यह एक असाधारण परिणाम है ... उन्होंने वास्तव में भूसे के ढेर में सुई ढूंढ ली है।' मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी एंडी रॉबर्टसन ने कहा कि कैप्सूल से किसी को किसी तरह की क्षति पहुंचने की सूचना नहीं है।

कैप्सूल से हो सकता है कैंसर

इसमें सीज़ियम 137 सिरेमिक स्रोत होता है, जो आमतौर पर विकिरण गेज में उपयोग किया जाता है, जो एक घंटे में 10 एक्स-रे प्राप्त करने के बराबर विकिरण की खतरनाक मात्रा का उत्सर्जन करता है। इससे त्वचा जल सकती है और लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर हो सकता है। खोज दल ने पूरे राजमार्ग की छानबीन करने में छह दिन लगाए। गत 10 जनवरी को एक रेगिस्तानी खदान स्थल और पर्थ के बीच ले जाते समय कैप्सूल गुम हो गया था।

कॉमनवेल्थ देशों से मांगी थी मदद

कैप्सूल ले जाने वाला ट्रक 16 जनवरी को पर्थ डिपो पहुंचा। आपातकालीन सेवाओं को 25 जनवरी को कैप्सूल के लापता होने की सूचना दी गई। खनन कंपनी रियो टिंटो आयरन ओर के मुख्य कार्यकारी साइमन ट्रॉट ने इस घटना के लिए माफी मांगी है। कैप्सूल के गायब होने की खबर सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया था। खोजी उपकरणों के अभाव में सरकार ने कैप्सूल को खोजने के लिए कॉमनवेल्थ देशों से मदद मांगी थी।

हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया हाई-टेक 110 सीसी स्कूटर - ज़ूम

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने आज नया 110 सीसी स्कटर-ज़ूम लॉन्च किया है। हीरो मोटोकॉर्प स्कूटर की श्रेणी को फिर से परिभाषित कर रही है और इसने स्कूटर सेगमेंट में तकनीक से लैस अपने सफर के नए चरण को पेश किया है। रोजाना के सफर में रोमांच और उत्साह की तलाश करने वाले संभावित उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए, ज़ूम को बेहद खूबसूरती और सावधानी से डिजाइन और विकसित किया गया है। ज़ूम स्कूटर समकालीन डिजाइन के साथ जबर्दस्त रफ्तार, बेमिसाल चपलता और असाधारण परफॉर्मेंस उपभोक्ताओं को प्रदान करता है। हीरो ज़ूम की 110 सीसी श्रेणी में एक नया रूप और डिजाइन पेश किया गया है। इंडस्ट्री में पहली बार नए फीचर के रूप में हीरो इंटेलिजेंट कॉर्नरिंग लाइट (एचआईसीएल) और सेगमेंट में पहली बार नए फीचर्स, बड़े और चौड़े टायर और 110 सीसी सेगमेंट में तेज रफ्तार के साथ यह स्कूटर अपने ओनर्स को बेमिसाल गतिशालता के अनुभव की गारंटी देता है। हीरो मोटोकॉर्प के चीफ ग्रोथ ऑफिसर (सीजीओ) रंजीवजीत सिंह ने कहा, 'पिछले कुछ सालों में हीरो मोटोकॉर्प ने प्रतिष्ठित ब्रैंड लॉन्च किए हैं, जिसने देश के लोगों को अपनी और आकर्षित किया है। हीरो मोटोकॉर्प का अपने उपभोक्ताओं से बेहतर और मजबूत जुड़ाव है। अपने बेमिसाल डिजाइन और हीरो ज़ूम की परफॉर्मेंस से हम अपने सफर में नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। नया हीरो ज़ूम युवा भारत की आवश्यकताओं को गहराई से समझने का नतीजा है। हमने स्कूटर में भविष्य को ध्यान में रखकर नई तकनीक को शामिल करने की प्रतिबद्ता बरकरार रखी है, जो हमारे स्कूटर के पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान करेगी। जो लोग स्कूटर की शानदार सवारी करना चाहते हैं और नए-नए फीचर्स से लैस स्कूटर को अपनाना चाहते हैं, वह निश्चित रूप से हीरो ज़ूम के जबर्दस्त और बोल्ड लुक की ओर आकर्षित होंगे।'

पाकिस्तान में हाहाकार... विदेश मुद्रा भंडार सूखने के करीब

भारत का लगातार दूसरे हफ्ते बढ़ा

मुंबई। एजेंसी

देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे हफ्ते बढ़ा है। 20 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान यह 1.727 अरब डॉलर बढ़कर 573.727 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी आई है। पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 10.417 अरब डॉलर बढ़कर 572 अरब डॉलर हो गया था। दूसरी ओर आर्थिक बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार 20 जनवरी को खत्म सप्ताह में 92.3 करोड़ डॉलर की गिरावट के साथ 3.67 अरब डॉलर रह गया। इससे केवल दो हफ्ते का आयात हो सकता है। पाकिस्तान ने घ्श्र से 22वीं बार कर्ज मांगा है लेकिन अब तक उसे यह पैसा नहीं मिला है।

अक्टूबर, 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक घटनाक्रमों के बीच केंद्रीय बैंक के रुपये की विनियम दर में तेज गिरावट को रोकने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग करने की वजह से बाद में इसमें गिरावट आई थी। अक्टूबर 2022 में, विदेशीमुद्रा भंडार में एक सप्ताह के दौरान 14.721 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। केंद्रीय बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा माने जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां समीक्षधीन सप्ताह में 83.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 506.358 अरब डॉलर हो गईं।

गोल्ड भंडार भी बढ़ा

डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाले विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पौंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं में आई घट बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व का मूल्य आलोच्य सप्ताह में 82.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 43.712 अरब डॉलर हो गया। आंकड़ों के अनुसार एसडीआर 6.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.432 अरब डॉलर हो गया। समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रखा देश का मुद्रा भंडार 10 लाख डॉलर घटकर 5.226 अरब डॉलर रह गया।

प्लास्टइंडिया 2023 में एसएबीआइसी के अभिनव समाधानों का प्रदर्शन किया गया

कार्बन न्यूट्रैलिटी में भारत की यात्रा को सहयोग देने के साथ ही प्लास्टिक्स की चक्रीयता पर ध्यान केन्द्रित करना

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अलग-अलग तरह के केमिकल्स में दुनिया की प्रमुख कंपनी एसएबीआइसी प्लास्टिक्स और रबर के बेहद अपेक्षित बड़े ट्रेड शो प्लास्टइंडिया 2023 में अपनी सुदृढ़ उपस्थिति दर्ज कराएगी। कोविड-19 महामारी से आई चुनौतियों के कारण यह आयोजन तीन साल बाद हो रहा है। नई दिल्ली में 1 से 5 फरवरी तक एसएबीआइसी प्रगति मैदान के हॉल 2, ग्राउंड फ्लोर, बी1 में अपने बूथ में अभिनव और स्थायी समाधानों का प्रदर्शन करेगी। यह समाधान दिखाएंगे कि एसएबीआइसी कैसे इलेक्ट्रिक परिवहन और चक्रीय अर्थव्यवस्था को गति देते हुए भारत की वृद्धि में योगदान दे सकती है और कार्बन न्यूट्रैलिटी के उसके लक्ष्यों में सहयोग दे सकती है। एसएबीआइसी में पेट्रोकेमिकल्स के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (ए) सामी अल-ओसाइमी ने कहा, 'तीन दशकों से भारत में एसएबीआइसी की मौजूदगी भारत के विकास की यात्रा के लिये हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है, साथ ही स्थायी और अभिनव समाधानों की आपूर्ति में आगे रहने की हमारी महत्वाकांक्षा भी प्रदर्शित करती है। इस क्षेत्र में हमारी टेक्नोलॉजी और नवाचार भारत में हमारे ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल व्यापक समाधन प्रदान करने पर केन्द्रित हैं और नवाचार के माध्यम से साथ-साथ बढ़ने पर एसएबीआइसी के फोकस पर जोर देते हैं। इन सब से भारत की स्थायी वृद्धि संभव होगी।' यह दिखाने के लिये, एसएबीआइसी प्लास्टइंडिया 23 में अपने स्थायी और उच्च प्रदर्शन वाले मटेरियल सॉल्यूशंस का प्रदर्शन करेगी, जोकि विभिन्न उद्योगों के लिये उपयुक्त हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कंज्यूमर गुड्स, फूड पैकेजिंग, सोलर पावर पैनल्स, 5जी नेटवर्क, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थकेयर सेक्टर।

ऑटोमोटिवः

एसएबीआइसी पुरस्कार-विजेता ईवी बैटरी पैक कवर प्रदर्शित करेगी, जोकि धातु से बनने वाले कवर की तुलना में 40% हल्का है और आग से सुरक्षा के कठोर मानकों पर खरा उतरता है। यह मटेरियल्स एसएबीआइसी की ब्लूहीरोरू पहल के अंतर्गत आते हैं, जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक पावर को अपनाना संभव बनाना और वाहन की क्षमता बढ़ाना है।

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्सः

भारत में 5जी सेवाओं के लिये मल्टीपोर्ट सर्विस टर्मिनल पार्ट्स और ऑप्टिक फाइबर केबल जैकेट्स की मांग है। एसएबीआइसी के सॉल्यूशंस, जैसे कि आग को धीमा करने वाला वालोक्सरू रेजिन अच्छा केमिकल और मेकैनिकल प्रतिरोध दिखाता है और एसएबीआइसी के बूथ पर प्रदर्शित होगा।

पैकेजिंगः

पुनःचक्रण के लिये बने टिकाऊ, लेकिन हल्के मोनो-मटेरियल सॉल्यूशंस और ऐप्लीकेशंस, जैसे कि चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले एसएबीआइसी बोप मटेरियल से बना नया और पूरी तरह से पुनःचक्रण के योग्य स्टैण्ड-अप पाउच, के इस्तेमाल द्वारा कचरे को कम करने पर लक्षित, का प्रदर्शन होगा।

बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शनः

जीवन की बेहतर गुणवत्ता और स्वस्थ रहन-सहन के लिये बढ़ती मांग में जरूरत को पूरा करने के लिये एसएबीआइसी लेक्सनरू और क्लिनिवालरू शीट्स की पेशकश करती है, जिनमें एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और झटके के लिये मजबूत प्रतिरोध है। इन्हें ऐसे समाधानों में इस्तेमाल किया गया है, जोकि अस्पतालों, चाइल्डकेयर और सार्वजनिक सुविधाओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। एसएबीआइसीरु वेस्टोलेन पी9421 सॉल्यूशन के साथ, एसएबीआइसी घरों के लिये ठंडे और गर्म पीने के पानी की आपूर्ति के लिये ऊष्मा को काफी हद तक सहन करने सकने वाले एसएबीआइसी मटेरियल से बने पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल की आपूर्ति को आसान भी बना सकती है।

नवीकरण योग्य ऊर्जाः

2030 तक नवीकरण योग्य ऊर्जा के लिये भारत के लक्ष्य ने सोलर कैपिसिटी के इंस्टालेशन की तेज वृद्धि में ईंधन का काम किया है। एसएबीआइसी सोलर फ्लोट्स के लिये एचडीपीई सॉल्यूशन के साथ बेहतरीन मेकैनिकल प्रॉपर्टीज वाले अपने पीओई सॉल्यूशंस दिखाएगी।

सामी अल-ओसाइमी ने आगे कहा, 'कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये हमारी प्रतिबद्धता जारी रखते हुए, एसएबीआइसी सउदी अरब, यूरोप, अमेरिका और एशिया-पैसिफिक में सोलर, विंड, हाइड्रोइलेक्ट्रिक और बायोमास इंस्टालेशंस के जरिये 4जीडब्ल्यू से ज्यादा नवीकरण योग्य ऊर्जा का इस्तेमाल करने पर केन्द्रित है। हम प्लास्टिक्स की चक्रीयता में सहयोग देने के लिये 2030 तक हर साल 1 मिलियन मेट्रिक टन ट्रूसर्कलरू सॉल्यूशंस का उत्पादन करने के लिये भी प्रतिबद्ध हैं। प्लास्टइंडिया 2023 एशिया की दूसरी सबसे बड़ी प्लास्टिक्स एवं रबर प्रदर्शनी है, जिसमें स्थायित्वपूर्णता और नवाचार पर खास ध्यान दिया जाएगा और इसमें दुनियाभर से 1800 से ज्यादा प्रदर्शकों के भाग लेने की उम्मीद है।

सयाजी होटल समूह, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सयाजी होटल समूह को इंदौर का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया। इस क्रिसमस ट्री को सयाजी के शेफ ने चॉकलेट से बनाया है। सयाजी इंदौर ने 17.850 फीट ऊंचे इस क्रिसमस ट्री को बनाने के लिए सही गुणवत्ता वाली चॉकलेट खोजने का विशेष प्रयास किया और अपनी इनोवेटिव सेवाओं के ज़रिये शहर में अपनी एक खास जगह बनाई है। सयाजी होटल्स के प्रबंध निदेशक, रऊफ धनानी ने बताया कि '' हमारी इस उपलब्धि के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हमें सम्मानित किया, जिसके लिए हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने 15 शेफ की एक टीम तैयार की थी, जिन्होंने क्रिसमस ट्री की वांछित ऊंचाई का निर्माण कुल 10 दिनों तक दिन-रात अथक काम करके पूरा किया। पिछले सम्मानितों के प्रतिष्ठित रैंकों में हमें जगह देना, हमारे लिए एक बड़ा सम्मान है।''

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक निर्विवाद क्यूरेटर है और भारतीय रिकॉर्ड्स का संरक्षक है जो लोगों को असाधारण उपलब्धियों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। सयाजी होटल समूह भारत का प्रमुख अपस्केल लाइफस्टाइल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है, जो अपने ग्राहकों के लिए खास सिग्नेचर हॉस्पिटैलिटी और लग्जरी के नए मानकों के लिए प्रसिद्ध है। सयाजी होटल समूह की प्रत्येक संपत्ति में ग्राहकों के लिए शानदार कमरे हैं। इसके अलावा, यहां दावत के आयोजन और खानपान एवं पेय की कई सुविधाएं उपलब्ध हैं।

सोने की सालाना मांग 2022 में पूरे दशक के नए उच्च स्तर पर पहुंची

नई दिल्ली। एजेंसी

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नई गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 2022 में सोने की सालाना मांग साल-दर-साल आधार पर 18 फीसदी बढ़कर 4,741 टन के स्तर पर पहुंच गई जो 2011 के बाद सर्वोच्च सालाना आंकड़ा है। चैथी तिमाही में रिकॉर्ड तेजी के कारण सोने की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इसकी मुख्य वजह केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई जबरदस्त खरीदारी और खुदरा निवेश में मजबूती रही केंद्रीय बैंकों की सालाना मांग 2022 में दोगुने से ज्यादा बढ़कर 1,136 टन रही जो एक वर्ष पहले 450 टन के स्तर पर थी और यह बढ़कर 55 वर्षों के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। वर्ष 2022 की सिर्फ चैथी तिमाही में हुई खरीदारी 417 टन के स्तर पर रही जिससे 2022 की दूसरी छमाही में हुई खरीदारी 800 टन से ज्यादा रही।

लुई स्ट्रीट सीनियर मार्केट एनालिस्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा पिछले वर्ष पूरे दशक के दौरान सोने की सालाना मांग सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई और इसकी मुख्य वजह निवेश के सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने में निवेश करने के लिए केंद्रीय बैंकों की बढ़ती मांग रही सोने की मांग बढ़ाने वाली अलग-अलग वजहें संतुलन के कारण बने क्योंकि ब्याज की बढ़ती दरों से ईटीएफ निकासी को बल मिला जबकि बढ़ती महंगाई ने सोने के बार और सिक्कों का निवेश बढ़ा। आखिर में कुल निवेश मांग पिछले वर्ष के मुकाबले 10 फीसदी बढ़ी। उन्होंने कहा अगर बात 2023 की हो तो आर्थिक अनुमान चुनौतीपूर्ण माहौल की ओर इशारा करते हैं और वैश्विक मंदी के भी संकेत मिल रहे हैं जिससे सोने के निवेश के रुझानों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर महंगाई दर नीचे आती है तो इससे सोने के बार और सिक्कों के निवेश में तेजी आ सकती है। इससे उलट, डॉलर में आई कमजोरी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की सुस्त रफ्तार का सोना आधारित ईटीएफ मांग पर सकारात्मक असर हो सकता है। हमें उम्मीद है कि ज्वेलरी की खपत मजबूत बनी रहेगी, चीन में लॉकडाउन खत्म होने से मांग में तेजी आएगी, लेकिन अगर मंदी का असर बढ़ा तो ग्राहकों के खर्च में कमी आने से सोने की मांग पर इसका असर हो सकता है हालांकि, इसके कई संभावित परिणाम हो सकते हैं लेकिन सोने ने हमेशा ही बुरे आर्थिक दौर में अच्छा प्रदर्शन किया है जिससे लंबी अवधि में इसके मूल्य और रणनीतिक असेट होने का पता चलता है। वर्ष 2022 में निवेश की मांग पिछले वर्ष के मुकाबले 10 फीसदी ज्यादा रही। इस बढ़ोतरी की मुख्य रूप से दो वजहें रहीं ईटीएफ निकासी में सुस्त निकासी और सोने के बार व सिक्कों की मजबूत मांग। पूरी दुनिया के कई देशों के निवेशकों के बीच सोने के बार और सिक्कों की मांग में तेजी जारी रही जिससे चीन के बाजारों में आई कमजोरी से निपटने में मदद मिली। 2022 के दौरान यूरोप में सोने के बार और सिक्कों का निवेश 300 टन का स्तर पार कर गया जिसकी मुख्य वजह जर्मनी में मांग में आई जबरदस्त तेजी रही। पश्चिमी एशिया में भी जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली, जहां सालाना मांग साल-दर-साल आधार पर 42 फीसदी बढ़ी।

वर्ष 2022 में ज्वेलरी की मांग में थोड़ी नरमी देखने को मिली जो 3 फीसदी गिरावट के साथ 2,086 टन रही। इस कमजोरी की मुख्य वजह चीन में ज्वेलरी की सालाना मांग में आई कमी रही। यह कमी 15 फीसदी रही क्योंकि साल भर ज्यादातर समय कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण ग्राहकों की गतिविधियां सीमित रहीं। चैथी तिमाही के दौरान सोने की कीमतों में आई तेजी की वजह से भी ज्वेलरी की मांग में सालाना गिरावट देखने को मिली। वर्ष 2022 में कुल सालाना आपूर्ति में क्रमिक सुधार जारी रहा और यह साल-दर-साल आधार पर 2 फीसदी बढ़कर 4,755 टन के स्तर पर पहुंच गया और महामारी से पहले के स्तर से ऊपर रहा। इसके अलावा, खान उत्पादन बढ़कर 3,621 टन हो गया जो चार वर्षों का उच्च स्तर है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।